

प्रेषक,

सुभाष कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून:दिनांक: 28 / 01 / 2009

विषय:—मै0 जे0पी0 रुडकी सीमेन्ट ग्राइंडिंग यूनिट को ग्राम नल्हेड़ी देहविरान भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में सम्पर्क मार्ग व पार्किंग हेतु कुल 1.234 है0 भूमि पट्टे पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6923/डी0एल0आर0सी0, दिनांक-29.12.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-198 तथा शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 में वर्णित प्राथमिकताओं में विचलन प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मै0 जे0पी0 रुडकी सीमेन्ट ग्राइंडिंग यूनिट को ग्राम नल्हेड़ी देहविरान भगवानपुर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में सम्पर्क मार्ग व पार्किंग हेतु कुल 1.234 है0 भूमि वर्तमान बाजार मूल्य के 2 गुने के बराबर नजराना एकमुश्त एवं नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया जमा कराये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
- (2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
- (4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

- (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (6) सम्बन्धित इकाई के लीज निष्पादन के पूर्व सम्बन्धित इकाई, ग्राम समाज एवं सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के मध्य एक कमिटीमेंट इस सम्बन्ध में आवश्यक होगा कि सम्बन्धित इकाई द्वारा ग्राम समाज के लिए सामुदायिक कार्यो यथा-बच्चों के खेलने के पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल आदि जैसा कि ग्राम समाज के लोग प्रस्तावित करें, सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित इकाई द्वारा किये जायेंगे।
- (7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों विन्दुसंख्या- 1 से 6 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)  
प्रमुख सचिव।

पू0प0सं0- 24 /संमदिनांकत/2009

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. श्री नौशाद अली, आर0एम0(लाईजन) ग्राम नल्हेड़ी देहविरान पोस्ट नल्हेड़ा अन्नतपुर, रुड़की जिला हरिद्वार।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)  
अनु सचिव।